आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 08.05.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया।
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा – असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखण्ड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। मानसून से पहले सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए।
- आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन।

राज्यपाल

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में आयोजित उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद की 17वीं बैठक में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि एक पवित्र दायित्व है। ऐसे बच्चे, जिनके पास संसाधनों, संरक्षण और अवसरों का अभाव है, उनके जीवन को संवारने के लिए संवेदनशील और सक्रिय प्रयास आवश्यक हैं। राज्यपाल ने परिषद के सदस्यों से अधिक उत्साह, सक्रिय सहभागिता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण परिषद जैसी संस्था को समय के अनुरूप नई सोच, नई कार्यशैली और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने प्रत्येक जिले में बाल कल्याण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर प्रभावी "बाल कल्याण केंद्र" विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक योजनाओं और सहायता का लाभ बेहतर ढंग से पहुंच सके। बैठक में राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद के वर्ष 2026–27 के अनुमानित आय और व्यय पर अनुमोदन करने के साथ ही विभिन्न बिंदुओं पर अपनी सहमति दी। बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया।

कृषि मंत्री

कृषि मंत्री गणेश जोशी इन दिनों असम दौरे पर हैं। उन्होंने असम के बरपाथार स्थित चाय बागानों का दौरा कर वहां की उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण प्रणाली और विपणन व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय चाय उत्पादकों, निर्यातकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर उत्तराखण्ड में चाय उत्पादन

को बढ़ावा देने, गुणवत्ता सुधारने और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में चाय उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य की जलवायु उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि असम के चाय उद्योग के अनुभवों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उत्तराखण्ड में भी चाय उत्पादन को नई दिशा देने का कार्य किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की चाय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी विपणन रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय किसानों को अधिक लाभ मिल सके।

केदारनाथ स्वच्छता

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा है कि यात्रा मार्ग, नदी और पहाड़ियों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, यात्रा मार्ग पर स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 से अधिक सफाई कर्मी सीतापुर से केदारनाथ धाम तक लगातार सफाई अभियान चला रहे हैं। अकेले गौरीकुंड क्षेत्र में 110 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। सोनप्रयाग में प्लास्टिक कचरे को कॉम्पैक्ट करने के लिए विशेष मशीनें लगाई गई हैं। अब तक लगभग केदारनाथ सहित यात्रा मार्ग पर सात टन प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर प्रोसेसिंग के बाद रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जा चुका है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर 600 से अधिक डस्टबिन लगाए हैं और पर्यावरण मित्रों की तैनाती कर नियमित सफाई और कचरा संग्रहण की व्यवस्था की है। ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी अनिल रावत ने श्रद्धालुओं से प्लास्टिक और अन्य कचरा निर्धारित कूड़ेदान में ही डालने की अपील की है।

वहीं , केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु भी सफाई व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की सराहना कर रहे हैं।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आगामी मानसून सीजन को लेकर सचिवालय में विभागों और जिलों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को मानसून पूर्व तैयारियां समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून के दौरान जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा भी संचालित हो रही है, ऐसे में सभी रेखीय विभागों को चौबीस घंटे अलर्ट मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मानसून शुरू होने से पहले सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करते हुए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही बिजली, पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शहरी विकास विभाग को भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राज्य में नदी तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए

नदियों के चैनलाइजेशन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने नदी मार्ग में जमा आरबीएम को हटाने के निर्देश दिए, ताकि नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो और कटाव से आबादी व आधारभूत संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, विनोद कुमार सुमन ने विभागीय तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में विभिन्न रेखीय विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है और मानसून अवधि के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

आकाशवाणी / वॉकथॉन

आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून से नेहरू कॉलोनी तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

राजयोग मेडिटेशन

चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में केंद्र सरकार की थीम "कर्मयोगी मिशन" के तहत राजयोग मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला जज, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से तनावमुक्त और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संबंधों में मधुरता और मानसिक शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन बेहद जरूरी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद उपयोगी साबित होते हैं।

धनराशि स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं के लिए 135 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने स्वीकृत धनराशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनहित के कार्यों में तेजी लाई जा सके।

स्वीकृत योजनाओं में विभिन्न ज़िलों में भवन निर्माण, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक भवनों के जीर्णोद्धार, पुलिस और होमगार्ड विभाग के कार्यों के साथ ही शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।